

स्वच्छता समाचार



जुलाई 2024



स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण

[@swachhbharat](#) [@SBMGramin](#) [@SwachhBharatMissionGramin](#) [@swachh_bharat](#) [@swachhbharatgrameen](#)



“स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। ये प्रयास हमें आश्चर्य करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है।”

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी
ने 27 जून, 2024 को संसद के संयुक्त सत्र
को संबोधित करते हुए कहा

कार्यक्रम की उपलब्धियां

28 जून, 2024 तक

ODF
PLUS

भारत के 2.04 लाख से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

- उदीयमान : 2,98,650
- उज्ज्वल : 42,436
- आर्दश : 2,04,185

3,34,504 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है

4,81,255 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है

275 निर्माणाधीन बायोगैस संयंत्र

709 कार्यशील बायोगैस संयंत्र

87 कार्यपूर्ण बायोगैस संयंत्र

3326 ब्लॉकों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है

स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियाँ (जून, 2024)

कोयला मंत्रालय:

- स्वच्छता एवं साफ-सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा, सभी कार्यालयों एवं खदानों में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।
- 16 जून 2024 को SECL मुख्यालय, बिलासपुर में CMD, SECL, SECL के कार्यकारी निदेशकों और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में स्वच्छता शपथ दिलाई गई।
- अरगडा स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में स्वच्छता शपथ ली गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

गेवरा:

- गेवरा में सहायक महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और सभी कर्मचारियों के साथ स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया।
- गेवरा कोयला खदान के आसपास के क्षेत्रों में कूड़ेदानों का वितरण किया गया ताकि निवासियों द्वारा कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके।
- गेवरा परियोजना के परिधीय गांवों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जल निकायों की नियमित सफाई के महत्व पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- कार्यक्रम की बेहतर समझ और अभिरूचि के लिए सामुदायिक नृत्य, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक जैसी सामुदायिक लामबंदी गतिविधियाँ आयोजित किए गए।
- गेवरा परियोजना से सटे स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छता पर केंद्रित शैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें निबंध लेखन, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं शामिल थीं।
- गेवरा में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया गया।
- सभी बाजारों में एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।



और शक्तिनगर और उर्जन के आसपास के क्षेत्रों में कपड़े के थैले भी वितरित किए गए।

कोरबा:

- कोरबा क्षेत्र की सभी खदानों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संबद्ध कार्यालयों, संगठनों और संस्थानों में स्वच्छता शपथ समारोह का आयोजन किया गया।

चिरमिरी:

- अस्पतालों, डिस्पेंसरियों के परिसरों की सफाई की गई तथा कूड़े-कचरे का निपटान किया गया।
- स्कूलों और खान विभाग के कार्यालयों की सफाई की गई तथा सभी कार्यालय परिसरों में नीले और हरे रंग के डस्टबिन रखे गए।
- सभी खदान प्रतिष्ठानों पर उपयुक्त IEC संदेश और बैनर लगाए गए।



सतत समाधान: केरल के एरट्टायार ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना



केरल के इडुक्की जिले के मनोहर परिदृश्य में अवस्थित, एरट्टायार ग्राम पंचायत सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहां अपशिष्ट प्रबंधन एक दोहरे समाधान के रूप में उभरा है: विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण।

राज्य के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति संसाधनों की वसूली और पुनर्चक्रण पर जोर देती है। हरित कर्म सेना के स्वयंसेवकों के नेतृत्व में डोर-टू-डोर संग्रह सेवाएं 4,600 से अधिक घरों और 500 संस्थानों तक पहुंचती हैं, जिससे लगभग 20,000 निवासियों के लिए कचरे का सुरक्षित और उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित होता है।

इसके अलावा, लगभग 30 स्थानीय महिलाओं को हरित कर्म सेना के माध्यम से रोजगार मिला है, वे औसतन 10,000 रुपये प्रति माह कमाती हैं। यह पहल न केवल स्वच्छता में योगदान देती है वरन लैंगिक असमानता को भी चुनौती देती है, समुदाय के भीतर समावेशिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। शुल्क संग्रह में हिचकिचाहट और बुनियादी ढांचे की असफलताओं सहित प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद, पंचायत की लचीली और अनुकूलन क्षमता ने प्रगति को प्रेरित किया है। पुनर्गठन के प्रयासों, उन्नत प्रशिक्षण और निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी ने अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियों को मजबूत किया है।

हरित कर्म सेना के 28 समर्पित सदस्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे डोर-टू-डोर संग्रह प्रणालियों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 85% परिवारों से और संस्थाओं से लगभग 90% उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह होता है, जिससे प्रति माह लगभग 2,50,000 रुपये का सृजन होता है।

[और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)



स्कूल मिड डे मील वेस्ट का रूपांतरण: पाइप कम्पोस्टिंग पहल



स्वच्छ भारत मिशन चरण-॥ गांवों में खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने और व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता को बढ़ाकर अपने प्रारंभिक चरण की सफलता पर निर्माण करना चाहता है। यह चरण ODF स्थिरता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा दृश्यगत स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देता है। छात्र, परिवर्तन के प्रमुख नायक के रूप में, इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों को शामिल करके, महत्वपूर्ण सामुदायिक परिवर्तन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे स्वीकार करते हुए, असम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मिशन निदेशालय ने 'पाइप कम्पोस्टिंग' के माध्यम से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन में छात्रों को शामिल करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है।

पाइप खाद की आवश्यकता

विभिन्न जिलों में 'गाँव सभाओं' के दौरान फोकस समूह चर्चा (FGD) ने एक आम मुद्दे पर प्रकाश डाला: मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निकलने वाले कचरे को अक्सर खुले में फेंक दिया जाता था, जिससे जल स्रोत दूषित हो जाते थे और पर्यावरण को नुकसान होता था। इस समस्या से निपटने के लिए, राज्य मुख्यालय ने जिला लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) अधिकारियों को मिड-डे मील योजना में भाग लेने वाले 42 प्रभागों में से प्रत्येक में 50 स्कूलों की पहचान करने का निर्देश दिया। स्कूल के अधिकारियों को 'पाइप कम्पोस्टिंग' विधि में प्रशिक्षित किया गया था, जो खाद्य अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक तकनीक है। यह विधि कार्बनिक पदार्थों को खाद बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी है, पोषक तत्वों से भरपूर खाद का उत्पादन करती है।

पाइपगत खाद: यह कैसे काम करता है

पाइपगत खाद बनाने की प्रक्रिया कचरे के दैनिक पृथक्करण के साथ शुरू होती है। जमीन की सतह पर पाइपगत खाद के लिए, तीन PVC पाइपों (लंबाई 1.5 मीटर और व्यास 150 मिमी) का उपयोग किया जाता है। पाइपों को रसोई के पास जमीन में डाला जाता है, उनकी आधी लंबाई भूमिगत होने के साथ 1-2 मीटर अलग होती है। भूमिगत भाग भूमि की ओर से खुला रहता है, जिसमें लीचिंग की अनुमति के लिए छोटे छेद होते हैं। प्रत्येक पाइप को बारिश के पानी और बाह्य सामग्रियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक उल्टे पुनःप्रयोज्य बैग के साथ कवर किया जाता है। बैग में वायु मार्ग के लिए छेद होता है।

[और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)



सतत अपशिष्ट प्रबंधन: बस्तर की कार्यशाला से अंतर्दृष्टि

राज्य स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला: ग्रामीण-शहरी सामंजस्य के लिए एक मॉडल



21 और 22 मई, 2024 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कुम्हरावंद में एसजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार और सहयोग का केंद्र बन गया। जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला ने "ग्रामीण और शहरी परिदृश्य सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त" परियोजना की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित किया, जो स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत स्थायी परिपाटियों के लिए नए मानक स्थापित करता है।

कार्यशाला में जिला प्रशासन बस्तर, HDFC बैंक, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE) और SWMS के सहयोगी प्रयासों के तहत बस्तर में स्थापित सामग्री वसूली सुविधा (MRF) पर प्रकाश डाला गया। यह सुविधा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी है, जो वर्तमान में बस्तर में लक्षित 114 गांवों में से 82 को जोड़ती है और ग्रामीण-शहरी अपशिष्ट प्रबंधन सामंजस्यता के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करती है।

कार्यशाला के पहले दिन पूरे छत्तीसगढ़ के जिला सलाहकारों और एसबीएम समन्वयकों सहित 63 प्रतिभागियों को प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के बारे में व्यापक ज्ञान देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इस कार्यक्रम ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित किया और बस्तर को अपशिष्ट प्रबंधन में ग्रामीण-शहरी सामंजस्यता के लिए एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया।

[और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)



#मासिक धर्म अनुकूल माहौल बनाना: झारखंड के नवागढ़ पंचायत में विश्व मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता दिवस



28 मई, 2024 को नवागढ़ पंचायत भवन में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, जो पहले कभी महसूस नहीं की गई। पहली बार, समुदाय विश्व मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता दिवस मनाने के लिए एक साथ सामने आया, पुरानी वर्जनाओं को तोड़ते हुए और एक ऐसे माहौल को अपनाते हुए, जहाँ मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा की जाती है और उसे वरीयता दी जाती है।

पीरामल फाउंडेशन के एक समर्पित गांधी फेलो श्री वृकचंदा सरकार द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और नीड्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम परिवर्तनकारी रहा। #पीरियड_फ्रेंडली_वर्ल्ड नामक थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 75 उत्साही किशोरियों, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामुदायिक जननेता शामिल हुए।

दिन की शुरुआत हार्दिक चेतना गीत के साथ हुई, "मुँह से कअिब जी न पाऊँगी, ज़रा सबसे ये कह दो", गीत के ये बोल पूरे आयोजन स्थल पर गूंजमान रहे जो सामाजिक बाधाओं और मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं को तोड़ने का प्रतीक था। इस जोरदार शुरुआत से खुली और ईमानदार चर्चाओं के लिए मंच तैयार किया गया।

चर्चा के दौरान, इस जनसमूह ने विश्व मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता दिवस के महत्व पर गहन चर्चा की तथा इस बात पर जोर दिया कि यह केवल सैनिटरी नैपकिन से कहीं अधिक महत्व रखता है। बातचीत में स्वच्छ स्थलों, पानी की सुविधा, व्यक्तिगत स्वच्छता और सैनिटरी पैड के उचित निपटान के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। जनसमुदाय को 28 मई की तारीख के बारे में बताया गया, जो औसत मासिक धर्म चक्र और अवधि को दर्शाता है, जो इस कारण के महत्व को रेखांकित करता है। चर्चा के दौरान किशोरियों ने अपने पहले मासिक धर्म के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने शुरुआती झिझक के साथ, अपनी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की, मासिक धर्म के इर्द-गिर्द अभी भी मौजूद सांस्कृतिक वर्जनाओं को उजागर करता है।

[और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)



युवाओं को सशक्त बनाना: राजसमंद के स्कूल एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी



राजसमंद, राजस्थान: प्लास्टिक कचरा एक वैश्विक समस्या है, जो न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कई जीवों और प्रजातियों को भी खतरे में डाल रहा है। यह ओजोन परत के विनाश और पृथ्वी के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि में योगदान देता है। प्लास्टिक का कोई व्यवहार्य विकल्प न होने के कारण, भविष्य की चुनौतियाँ बड़ी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण राजस्थान ने प्लास्टिक कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित करके प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रित करने की परियोजना शुरू की है।

जिला परिषद राजसमंद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों के साथ प्लास्टिक कचरे के निपटान की कार्यनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान, खुले में बिखरे प्लास्टिक कचरे, विशेष रूप से पानी की बोतलों को इकट्ठा करने और इसे तत्काल निपटान के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया। विकास अधिकारियों को इस योजना को लागू करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ सरकारी निर्देश प्राप्त हुए।

और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



झारखंड के पाइका गांव की ODF Plus की उदीयमान श्रेणी की ओर अग्रसर प्रेरणादायक यात्रा



पाइका गांव जल स्वच्छता और सफाई के क्षेत्र में बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा है, जो व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव और समर्पण को दर्शाता है। स्थानीय जल सहायता उर्मिला देवी के नेतृत्व में, गांव ने ODF Plus का दर्जा हासिल करने की दिशा में यात्रा शुरू की, जो एक स्थायी, खुले में शौच मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शुरुआती दिनों में, पाइका को खराब स्वच्छता प्रथाओं से जूझना पड़ा, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जलजनित बीमारियाँ फैलती थीं, खासकर बच्चों में। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के शुभारंभ ने बदलाव की शुरुआत की। पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया और खुले में शौच की प्रथा पर अंकुश लगाया गया। हालाँकि, इस नई स्वच्छता को बनाए रखना नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था।

SBM-G के दूसरे चरण ने पाइका के स्वच्छता आंदोलन को नई गति दी। जिला और ब्लॉक स्तरीय टीमों द्वारा प्रशिक्षित उर्मिला देवी ने समुदाय को ODF वातावरण बनाए रखने और ODF Plus स्थिति में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। इसमें न केवल शौचालयों का उपयोग शामिल था, बल्कि प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल था।

उर्मिला की यात्रा बिना किसी रुकावट के नहीं रही। ग्रामीणों को घरेलू शौचालयों के उपयोग और कचरा प्रबंधन के महत्व के बारे में समझाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता थी। उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग किया, स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों से संपर्क किया और सामुदायिक बैठकें आयोजित कीं। उनकी पहल को जिले के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा सहयोग दिया गया, जिसने बायोडिग्रेडेबल कचरा और गंदला जल के प्रबंधन के लिए खाद के गड्ढे और सोखने वाले गड्ढों जैसे उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान की।

ग्रामीणों ने उनके मार्गदर्शन में, ODF Plus श्रेणी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की, जिसे पंचायत और जिला प्राधिकारियों ने उन्हें स्वीकृति प्रदान की।

[और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)



राज्य के झरोखे से

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत, उत्तराखंड विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से प्लास्टिक कचरे का समुचित निपटान और घरेलू स्तर पर कचरे को अलग करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरंतर प्रगति कर रहा है। ब्लॉक स्तर पर, प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा निर्मित शेड और पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान की गई कॉम्पैक्टिंग मशीनें उपलब्ध हैं। जिला पंचायतें इन केंद्रों के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें कई महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिन्हें "पर्यावरण सखी" के रूप में जाना जाता है, सक्रिय रूप से शामिल हैं।

एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में, उत्तराखंड में आगंतुकों की एक महत्वपूर्ण संख्या देखी जाती है। प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, विशेष रूप से यात्रा मार्गों और उच्च हिमालयी पर्यटन क्षेत्रों में, काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है।

लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली चारधाम यात्रा के दौरान, रास्ते में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये परिसर आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करते हैं और ग्राम पंचायतों, व्यापार मंडलों और मंदिर समितियों द्वारा स्वच्छता बनायी रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण पशु चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर पशु अपशिष्ट सहित ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करता है।

विकसित भारत यात्रा के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण ने स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई है। ODF Plus मॉडल श्रेणी हासिल करने वाले गांवों के ग्राम प्रधानों को अभिनंदन पत्रों से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार किया और ODF Plus स्थिति हासिल करने के लिए अधिकांश जिलों का नेतृत्व किया।

गंगा नदी के उद्गम स्थल उत्तराखंड के गोमुख में नमामि गंगे अभियान के तहत स्वच्छता के प्रयास जारी हैं। इसमें अनुपचारित जल को नदी में प्रवेश करने से रोकना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी गंगा ग्राम ODF Plus स्थिति तक पहुंचें, जिसमें 87% ODF Plus मॉडल का श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं।



स्वच्छता प्रयासों को बनाए रखने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में स्वास्थ्य और साफ-सफाई शिक्षा पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित किया गया है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके, ये पहल बच्चों को उचित स्वच्छता की आदतों को जल्दी अपनाने में मदद करती हैं। स्वच्छता सेल्फी और स्वच्छता नारे जैसे अभियान जागरूकता को और बढ़ावा देते हैं।

श्री आलोक कुमार पांडे (आईएएस)

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण/निदेशक स्वजल
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
उत्तराखंड सरकार



विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की झलकियां



अंतर को पहचानें: क्लीन विलेज एडिशन

क्या आप इन दोनों गांवों में अंतर पहचान सकते हैं? इनमें से एक साफ-सुथरा और व्यवस्थित है जबकि दूसरे में स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तस्वीरों को ध्यान से देखें और अंतर पर गोला बनाएं।



शुभकामनाएं, याद रखें- गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग अहम होता है।



सचिव की कलम से



श्रीमती विनी महाजन,

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के 10वें वर्ष की दूसरी तिमाही में प्रवेश करते हुए, हम सभी को अपने मिशन की सफलता के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करना होगा। हमें अपने प्रयासों में गति लानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ज़मीन पर किए जा रहे काम वास्तव में उन समुदायों की जरूरतों और आवाज़ों को दर्शाते हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। हमारी स्वच्छता पहल प्रासंगिक और प्रभावी तथा स्थायी बनी रहनी चाहिए।

हम सभी हितधारकों- सरकारी अधिकारियों, स्थानीय नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे मिलकर काम करें और जो गति हमने बनाई है उसे आगे बढ़ाएं। एक साथ मिलकर, हम सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम नवाचार, समावेशिता, पारदर्शिता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हम वास्तव में 'सम्पूर्ण स्वच्छ भारत' के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस 10वें वर्ष को एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की ओर हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित करें।

मिशन निदेशक की कलम से



श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM-G),
DDWS, जल शक्ति मंत्रालय

"जैसे-जैसे हम अपने स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम नए विचारों को पेश करने और नवीन साझेदारियाँ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षाविदों और अलग-अलग हितधारकों के साथ सहयोग करके, हमारा लक्ष्य सभी के लिए एक गतिशील शिक्षण प्रक्रिया तैयार करना है। हमारा लक्ष्य स्वच्छता को एक आवश्यकता से बढ़ाकर एक साझा सामाजिक जिम्मेदारी बनाना है, जिससे यह सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए। हम जन आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो। बड़ी हुई सामुदायिक भागीदारी, अत्याधुनिक शोध और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से, हम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देंगे जहाँ स्वच्छता को सर्वव्यापी रूप से वरीयता दी जाती है। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल हमारे प्रयासों को बनाए रखेगा बल्कि उन्हें बढ़ाएगा, जिससे सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ भारत सुनिश्चित होगा।"

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की
15 तारीख से पहले swachhbharat@gov.in पर अपनी प्रस्तुति साझा करें।

